

09.08.2010 को जारी एजिस्टर्ड दरतावेज के रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 लीलादेवी से भूमि

ही यह भी जाहिर किया कि रेस्पॉडेन्ट बेनीया द्वारा अपन 2/5 हिस्से की भूमि दिनांक 3/प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 एवं अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा होना जाहिर किया, साथ हीसा, प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पॉडेन्ट संख्या 2 का 2/5 हिस्सा, रेस्पॉडेन्ट संख्या संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई स्थित है, जिसमें वादीया/रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 का 1/5 प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया कि ग्राम जंसावास में वादीया एवं प्रतिवादीगण की संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 का विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पॉडेन्ट

अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पेश की गई। अपील दर्ज एजिस्टर कर रेस्पॉडेन्ट को जारी सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद संख्या 86/2010 में पारित निर्णय एवं डिफ़ी दिनांक 25.04.2013 के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर बगौडा द्वारा अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223

दिनांक:- 9.4.18

:- निर्णय :-

उपरिस्थित :-  
 श्री जगदीश गोदार, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट  
 श्री निखिल दत्त, विद्वान अभिभाषक रेस्पॉडेन्ट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



अपीलान्ट	बनाम	रेस्पॉडेन्ट :-
नारणा पुत्र मोती जालि कलबी	जिला जालौर	लीलादेवी उर्फ रम्भादेवी पत्नी
निवासी जंसावास तहसील बगौडा	जिला जालौर	मनरुपाराम जालि कलबी निवासी
जिला जालौर	जिला जालौर	जंसावास तहसील बगौडा
2	बेनीया पुत्र मोती	
3	भनीया पुत्र मोती जालियान कलबी	निवासीगण जंसावास तहसील
	बगौडा जिला जालौर	
4	राज्य सरकार जालिये तहसीलदार	बगौडा जिला जालौर

राजस्व अपील : 16/2013

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालौर  
 पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.



4

6. आया वादग्रस्त आराजी बाबत श्रीमान सेशन न्यायाधीश भीनमाल द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.07.209 की परवान किए बिना वादग्रह भूमि का हस्तान्तरण किया है, जिससे वाद काबिल खरिज है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

5. आया वादीया का खसरा नम्बर 275 रकबा 2.72 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 490 पर एक अजनबी केला के नाते मौके पर कब्जा काबत नहीं होने से वादीया अन्यत्र धाबित कराने तथा उक्त आराजी अपने बेट में निश्चित भू भाग का बंटवाला करवाने की अधिकांश नहीं है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

4. आया वादग्रस्त आराजी में ख0 हटिया की 1/5 की शामलाती खातेदासी भूमि पर उसके गोदपुत्र हरदाना का कब्जा है। शामलाती खातेदासी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 वेलीया ने अपने एक में दिनांक 08.08.2008 को तर्कनामा करया है, जिसे रद्द करना बाबत दीवानी वाद संख्या 1/2009 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भीनमाल में पेश किया हुआ है, जिससे वादीया का वाद चलने योग्य नहीं है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

3. आया वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 13.68 हेक्टेयर में वादीया का 1/5 हिस्सा की शामलाती खातेदासी होने से वादीया बिना बंटवाला कब्जा प्राप्त करने की अधिकांश नहीं है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

2. आया उक्त वर्णित आराजी पर वादीया अपने हिस्से पर काबिल अनुसार मौलिक विमानन कराकर खातेदासी दर्ज करवाने की अधिकांश है तथा साथ ही अपने कब्जे काबत बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकांश है ? जिम्मे वादीया

1. आया मौजा जेसावास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 9.75 हेक्टेयर में से 2.72 हेक्टेयर दक्षिणी पूर्वी कोने पर स्थित एवं खसरा नम्बर 490 रकबा 3.77 हेक्टेयर का समूर्ण हिस्सा दावे के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही में वर्णित आराजी वादीया अपनी खातेदासी धाबित कराने की अधिकांश है ? जिम्मे वादीया



तनकीयात कायम की गई, जो इस प्रकार है -  
 6 को नकारते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 डकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा वाद पत्र के तथ्यों करताते हुए विमानन कराने का अनुरोध चाहा। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कर अपनी खरीदरुदा भूमि में से अपने एक हिस्से की भूमि की पृथक से खातेदासी धाबित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेसुडेन्ट संख्या 1 द्वारा बतौर वादीया वाद प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 4 व 6 में कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण उनका विनिश्चय समुचित नियमों एवं सन्दर्भ आंकित करते हुए किया जाना था, जो नहीं किया गया तथा साथ ही भूमि के सम्बन्ध में दीवानी वाद विचारधीन रहते राजस्व वाद किस हद तक प्रभावित होता है, इस बिन्दु को भी अधीनस्थ न्यायालय को रेखांकित करते हुए विस्तृत विवेचन किया जाना था, जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जिस रूप में तनकीयात को विनिश्चित किया गया है, उसे विधि अनुसार नहीं माना जा सकता है। विधि अनुसार समस्त तनकीयात को पृथक पृथक रूप से विनिश्चित किया जाना आडोपक है, जिसका जोर अपील निर्णय में पूर्णतः अभाव पाया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जोर अपील निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।



परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा राजस्व वाद संख्या 86/2010 में न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्लीटिनांक 25.04.2013 को अपस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रिष्ठित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उपरोक्त Observation को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को सनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/02-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

कैम्प जालौर  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)

*(Handwritten signature)*